

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 915]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2019 — पौष 10, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 दिसम्बर 2019

अधिसूचना  
सं. 74 / 2019—राज्य कर

क्रमांक एफ-10-50/2019/वाक/पांच (123).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना संख्या 4/2018-राज्य कर, क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच(3), दिनांक 24 जनवरी, 2018, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 31-अ, तारीख 25 जनवरी, 2018 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो मास/तिमाही जुलाई, 2017 से नवंबर, 2019 तक के लिए, देय तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 19 दिसंबर, 2019 से 10 जनवरी, 2020 तक की बीच की अवधि के उक्त ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में दे दिए हैं।”।

2. यह अधिसूचना 19 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 27 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-50/2019/वाक/पांच(123).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-50/2019/वाक/पांच (123), दिनांक 27-12-2019 का अग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 27th December 2019

**NOTIFICATION**  
No. 74/2019 – State Tax

No. F-10-50/2019/CT/V (123).— In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 4/2018-State Tax, No. F-10-2/2018/CT/V(3), dated the 24th January, 2018 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 31-A, dated the 25th January, 2018, namely:-

In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the amount of late fee payable under Section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the details of outward supplies in FORM GSTR-1 for the months/quarters from July, 2017 to November, 2019 by the due date but furnishes the said details in FORM GSTR-1 between the period from 19th December, 2019 to 10th January, 2020.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 19th day of December, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 27 दिसम्बर 2019

अधिसूचना  
सं. 75 / 2019—राज्य कर

क्रमांक एफ-10-50/2019/वाक/पांच (124).— राज्य सरकार, माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 36 के उपनियम (4) में, 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी, “20 प्रतिशत” अंक और शब्द के स्थान पर “10 प्रतिशत” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 86 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“86क. इलैक्ट्रानिक जमा खाते में उपलब्ध रकम के उपयोग की शर्तें.-

(1) आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो सहायक आयुक्त की श्रेणी से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इलैक्ट्रानिक जमा खाते में उपलब्ध इनपुट कर के प्रत्यय का कपटपूर्वक उपभोग किया गया है या वह अपात्र है, उस सीमा तक जिस तक वह-

क) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग,-

(i) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जिसे अस्तित्वहीन पाया गया है या जो ऐसे किसी स्थान से, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप किया गया है, कोई कारबाह नहीं चला रहा है, द्वारा जारी ; या

(ii) माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति के बिना,

कर बीजकों या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर किया गया है ; या

ख) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग, किसी ऐसे प्रदाय के संबंध में जिसकी बाबत प्रभारित कर सरकार को संदर्भ नहीं किया गया है ; कर बीजकों या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर किया गया है ; या

ग) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अस्तित्वहीन पाया जाता है या ऐसे किसी स्थान से, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, कोई कारबार नहीं चला रहा है; या

घ) इनपुट कर के किसी प्रत्यय का उपभोग करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कब्जे में कर बीजक या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित कोई अन्य दस्तावेज नहीं है,

लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, धारा 49 के अधीन किसी दायित्व के निर्वहन के लिए या किसी अनुपयोजित रकम के किसी प्रतिदाय के दावे के लिए इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में से ऐसे प्रत्यय के समतुल्य किसी रकम का विकलन अनुज्ञात नहीं कर सकेगा।

(2) आयुक्त या उपनियम (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यह समाधान हो जाने पर कि इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते के विकलन को अनुज्ञात करने की यथा उपरोक्त शर्त अस्तित्व में नहीं है, ऐसे विकलन को अनुज्ञात कर सकेगा।

(3) ऐसे निर्बन्धन, उस तारीख से, जिसको ऐसे निर्बन्धन अधिरोपित किए जाएं, एक वर्ष की अवधि की समाप्त के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेंगे।

4. उक्त नियमों में, 11 जनवरी, 2020 से प्रभावी, नियम 138डॉ में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति ने, यथास्थिति, दो मास के लिए या दो तिमाही के लिए जावक प्रदायों का विवरण नहीं दिया है।"

5. यह अधिसूचना 26 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 27 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-50/2019/वाक/पांच(124).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-50/2019/वाक/पांच (124), दिनांक 27-12-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 27th December 2019

**NOTIFICATION**  
**No. 75/2019 – State Tax**

No. F-10-50/2019/CT/V (124).— In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2019.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the of this notification.
2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from the 1st January, 2020, in rule 36, in sub-rule (4), for the figures and words "20 per cent.", the figures and words "10 per cent." shall be substituted.
3. In the said rules, after rule 86, the following rule shall be inserted, namely:-

"86A. Conditions of use of amount available in electronic credit ledger.-

(1) The Commissioner or an officer authorised by him in this behalf, not below the rank of an Assistant Commissioner, having reasons to believe that credit of input tax available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible in as much as-

- a) the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other document prescribed under rule 36-
  - i. issued by a registered person who has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained; or
  - ii. without receipt of goods or services or both; or

- b) the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other document prescribed under rule 36 in respect of any supply, the tax charged in respect of which has not been paid to the Government; or
- c) the registered person availing the credit of input tax has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained; or
- d) the registered person availing any credit of input tax is not in possession of a tax invoice or debit note or any other document prescribed under rule 36,

may, for reasons to be recorded in writing, not allow debit of an amount equivalent to such credit in electronic credit ledger for discharge of any liability under Section 49 or for claim of any refund of any unutilised amount.

(2) The Commissioner, or the officer authorised by him under sub-rule (1) may, upon being satisfied that conditions for disallowing debit of electronic credit ledger as above, no longer exist, allow such debit.

(3) Such restriction shall cease to have effect after the expiry of a period of one year from the date of imposing such restriction.”.

4. In the said rules, with effect from the 11th January, 2020, in rule 138E, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

“(c)being a person other than a person specified in clause (a), has not furnished the statement of outward supplies for any two months or quarters, as the case may be.”.

5. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 26th day of December, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.

अटल नगर, दिनांक 27 दिसम्बर 2019

आदेश  
सं. 10/2019—राज्य कर

क्रमांक एफ-10-50/2019/वाक/पांच (125).— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् आने वाले इकतीस दिसंबर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन में करदाताओं को कुछ तकनीकी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालावधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी है और जिसके कारण उक्त धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कठिपय कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं।

अतः, अब, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर, कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम—इस आदेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (कठिनाईयों को दूर करना, दसवां) आदेश, 2019 है।
2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 के स्पष्टीकरण में, “31 दिसंबर, 2019” अंकों और शब्द के स्थान पर “31 जनवरी, 2020” अंक और शब्द रखे जाएंगे।
2. यह आदेश 26 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 27 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ-10-50/2019/वाक/पांच(125).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-50/2019/वाक/पांच(125), दिनांक 27-12-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 27th December 2019

ORDER  
No. 10/2019 – State Tax

No. F-10-50/2019/CT/V (125).— Whereas, sub-section (1) of Section 44 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under Section 51 or Section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year;

And Whereas, for the purpose of furnishing of the annual return electronically for every financial year as referred to in sub-section (1) of Section 44 of the said Act, certain technical problems are being faced by the taxpayers as a result whereof, the said annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 could not be furnished by the registered persons, as referred to in the said sub-section (1) and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said Section.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 172 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017, the State Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:—

1. Short title.—This Order may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Tenth Removal of Difficulties) Order, 2019.
2. In Section 44 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017, in the Explanation, for the figures, letters and word “31st December, 2019”, the figures, letters and word “31st January, 2020” shall be substituted.
2. This Order shall be deemed to have come into force with effect from the 26th day of December, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.